क़ीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ–37, अंक – 15 | अगस्त 1–15, 2023 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ–4

समान नागरिक संहिता पर बहस :

प्रगतिशील सुधार की आड़ में लोगों को बांटने का अभियान

14 जून को, हिन्दोस्तान के 22वें विधि आयोग ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी करके, समान नागरिक संहिता (यूनिफार्म सिविल कोड – यू.सी.सी.) के बारे में राय और विचार मांगे। आयोग ने ऐसे विचार प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों की समय सीमा जारी की। नागरिक संहिता विवाह, तलाक, भरण–पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने जैसे सामाजिक अथवा पारिवारिक मामलों को नियंत्रित करने वाले क़ानूनों को परिभाषित करती है।

कुछ दिनों बाद, मध्य प्रदेश में बूथ–स्तरीय भाजपा कार्यकर्ताओं से बात करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने यू.सी.सी. का आह्वान किया। विभिन्न धार्मिक समुदायों के अलग–अलग क़ानूनों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने पूछा कि देश "दोहरी व्यवस्था" के साथ कैसे चल सकता है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री हिंदू और मुस्लिम समुदायों के अलग–अलग पारिवारिक क़ानूनों की तरफ़ इशारा कर रहे थे।

एक समान क़ानून की ज़रूरत पर बहस शुरू कर दी गई है, बिना यह बताए कि वह क़ानून क्या होना चाहिए। प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का कोई मसौदा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस पर विचार–विमर्श किया जा सके।

सभी धार्मिक विचारों और देश के सभी इलाकों की महिलाएं अपने ख़िलाफ़ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए सामाजिक मामलों से संबंधित क़ानूनों में सुधार के लिए लंबा संघर्ष करती रही हैं। महिलाएं यह मांग करती रही हैं कि क़ानून को उन सारे अधिकारों को मान्यता देनी चाहिए व उनकी हिफ़ाज़त करनी चाहिए, जो मनुष्य होने और विवाह व परिवार में बराबर के भागीदार होने के नाते, महिलाओं को मिलने चाहियें। इस संघर्ष का सभी प्रगतिशील ताक़तों ने समर्थन किया है।

वर्तमान में, हमारे देश के लोगों के सामाजिक संबंध विभिन्न धर्मों और पारंपरिक रीति–रिवाजों पर आधारित कई अलग–अलग, सामाजिक मामलों से संबंधित क़ानूनों के तहत, नियंत्रित होते हैं। जबकि प्रधानमंत्री ने "दोहरी व्यवस्था" की बात की, तो ज़मीनी तौर पर सामाजिक मामलों से संबंधित क़ानूनों की दो से अधिक, कई अलग–अलग व्यवस्थाएं हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, कई आदिवासी लोगों आदि पर अलग–अलग क़ानून लागू होते हैं। कुछ आदिवासी लोग संपत्ति विरासत के लिए मातृसत्तात्मक व्यवस्था का पालन करते हैं। कुछ सामान्य क़ानून भी हैं, जैसे कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954, जो कोई धार्मिक समारोह न चाहने वालों को विवाह का क़ानूनी तरीक़ा दिलाता है।

धर्म पर आधारित सभी सामाजिक मामलों से संबंधित क़ानून पुरुष–प्रधानता के पुराने विचारों पर आधारित हैं। ये महिलाओं के ख़िलाफ़ भेदभाव करते हैं। ये क़ानून पुरुषों और महिलाओं को तलाक, बच्चा गोद लेने, भरण–पोषण, संतान की अभिभावकता और संपत्ति की विरासत के मामलों में समान अधिकारों के साथ, समान भागीदार के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। कुछ सामान्य क़ानूनों में भी समस्याएं हैं। मिसाल के तौर पर, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह की सूचना देने के बाद 30 दिन की बाध्यकारी नोटिस अवधि, दम्पति के परिवार के सदस्यों को हस्तक्षेप करने और विवाह को रोकने की संभावना देती है।

सभी धार्मिक विचारों और देश के सभी इलाकों की महिलाएं अपने ख़िलाफ़ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए सामाजिक मामलों से संबंधित क़ानूनों में सुधार के लिए लंबा संघर्ष करती रही हैं। महिलाएं यह मांग करती रही हैं कि क़ानून को उन सारे अधिकारों को मान्यता देनी चाहिए व उनकी हिफ़ाज़त करनी चाहिए, जो मनुष्य होने और विवाह व परिवार में बराबर के

शेष पृष्ठ 3 पर

राजस्थान के किसानों की शानदार जीत

राजस्थान के नोहर और भादरा तहसील के किसान अमरसिंह ब्रांच से पानी चोरी के ख़िलाफ़ लंबा संघर्ष चलाते आये हैं। यह संघर्ष अमरसिंह ब्रांच संघर्ष समिति भादरा–नोहर की अगुवाई में लगातार चलता रहा है। लोक राज संगठन की राजस्थान इकाई ने इस संघर्ष को सफल करने के लिये पुरजोर काम किया है।

किसानों के धरने और प्रदर्शन के कारण प्रशासन को मजबूरन किसानों की मांगों को मानने के लिये वार्ता करनी पड़ी। यह वार्ता 18 जुलाई, 2023 को अमरसिंह ब्रांच संघर्ष समिति भादरा–नोहर के नेताओं और नायब तहसीलदार, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता की उपस्थिति में हुई।

वार्ता के दौरान दोनों पक्षों में यह समझौता हुआ कि सिंचाई विभाग मोघों को दुरुस्त करने के लिये एक सप्ताह के भीतर टेंडर निकालेगा तथा सभी वित्तीय और प्रशासनिक समस्याओं को दूर करेगा। सिंचाई विभाग की ओर से किसानों से यह वादा किया गया कि मोघों को दुरुस्त करके निर्धारित क्षमता के अनुसार पानी देना सुनिश्चित किया जायेगा। पानी चोरी रोकने के लिये प्रभावी क़दम उठाये जायेंगे।

मज़दूर एकता लहर किसानों के इस संघर्ष को लेकर लगातार रिपोर्ट करता आया है कि उप–तहसील रामगढ़ के किसान और अमरसिंह ब्रांच के तहत आने वाले अन्य गांवों के किसान अपनी मांगों – सिंचाई के लिये पानी की पर्याप्त आपूर्ति व अवैध मोघों को बंद करना तथा नहर से पानी की चोरी को रोकने – के लिये लगातार संघर्ष करते आये हैं।

विदित है कि किसानों ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन 18 जून, 2023 को नायब तहसीलदार को सौंपा था। उनके ज्ञापन में स्पष्ट कहा गया था कि एक सप्ताह के भीतर मोघों की समस्याओं को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को तेज़ किया जायेगा। एक सप्ताह बाद भी जब प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की तो किसानों ने धरना शुरू कर दिया।

यह धरना 26 जून से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलता रहा, जिसके चलते प्रशासन को किसानों के सामने झुकना पड़ा और उनकी मांगें माननी पड़ीं। इसमें प्रत्येक दिन अलग–अलग गांवों के किसान क्रमिक रूप से शामिल होते रहे हैं। रामगढ़, बरवाली, परलीका, गोगामेढ़ी, ढिलकी जाटान, दीपलाना, बडबिराना, नेठराना, आदि गांवों के किसान शामिल हुये।

याद रखा जाये कि अमरसिंह ब्रांच नहर में अवैध मोघों की वजह से इस क्षेत्र के कई गांवों की फ़सलें प्रभावित होती हैं। बिजाई के समय पर्याप्त पानी न मिलने के कारण फ़सलों की बुआई में देरी हो जाती है।

किसानों की जीत के लिये हम उनके संघर्ष को सलाम करते हैं। लेकिन किसानों को सर्तक रहना होगा कि राज्य और उसका प्रशासन वादा तो कर देते हैं, लेकिन वे अपने वादे से बार–बार मुकर जाते हैं। यह इसलिये होता है क्योंकि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, ये सिर्फ़ पूंजीपति वर्ग

शेष पृष्ठ 3 पर

अंदर पढ़ें

- डॉलर के वर्चस्व के ख़िलाफ़ प्रयास 2
- ब्रिटेन में डॉक्टरों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल की 3

डॉलर के वर्चस्व के ख़िलाफ़ प्रयास

कई देश अमरीकी डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के तरीके विकसित करने में लगे हुए हैं। उसके अनुसार वे अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर के अनुपात को भी कम कर रहे हैं। ऐसे सब क़दम दुनिया की आरक्षित मुद्रा बतौर अमरीकी डॉलर के प्रभुत्व को कम करने के प्रयासों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे उस प्रवृत्ति का हिस्सा हैं जिसे डी–डॉलराईजेशन कहा जाने लगा है।

पिछली सदी के अंत में, यूरोपीय संघ की आम मुद्रा बतौर यूरो के आने के साथ ही अमरीकी डॉलर के प्रभुत्व में कमी होनी शुरू हो गई थी। इराक और लीबिया जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने अमरीकी डॉलर के बजाय यूरो में अपना तेल बेचना शुरू कर दिया था। अमरीकी साम्राज्यवाद ने पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाकर और बाद में आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ने के बहाने, उन देशों के ख़िलाफ़ सैन्य हस्तक्षेप करके ऐसे क़दमों को रोक दिया। परन्तु ऐसे आक्रामक उपायों ने बढ़ती संख्या में अन्य देशों द्वारा डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के प्रयासों को नहीं रोका है।

अमरीकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने का एक प्रमुख कारण अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा इसे आर्थिक और भू–राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना है। जिन देशों को अमरीका अपना विरोधी मानता है, उन्हें व्यापारिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है और उनके डॉलर खातों को फ्रीज़ कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, वेनेजुएला शासन को अमरीकी सरकार द्वारा नाजायज़ घोषित कर दिया गया है। वेनेजुएला के सेंट्रल बैंक को वेनेजुएला के लोगों की ज़रूरत की वस्तुओं के आयात के लिए अपने डॉलर भंडार का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ऐसे अमरीकी प्रतिबंधों का सामना करने वाले अन्य देशों में उत्तर कोरिया, ईरान, अफ़ग़ानिस्तान, क्यूबा, म्यांमार, रूस और सीरिया शामिल हैं।

डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की चाहत रखने वाले देशों का दूसरा प्रमुख कारण अमरीकी सरकार का भारी और बढ़ता क़र्ज़ है। अमरीकी सरकार अपने भारी सैन्य खर्च उठाने के लिए डॉलर उधार लेती रहती है और नये डॉलर छापती रहती है। वह अपने पिछले क़र्ज़ को चुकाने के लिए और अधिक उधार लेती रहती है। इससे अमरीकी डॉलर की क्रय शक्ति से जुड़ा जोखि़म बढ़ गया है।

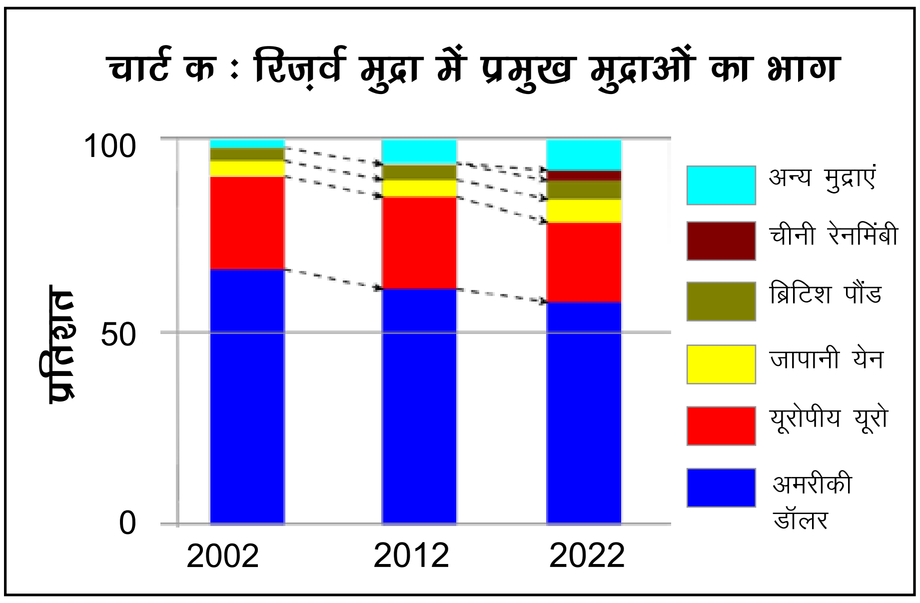

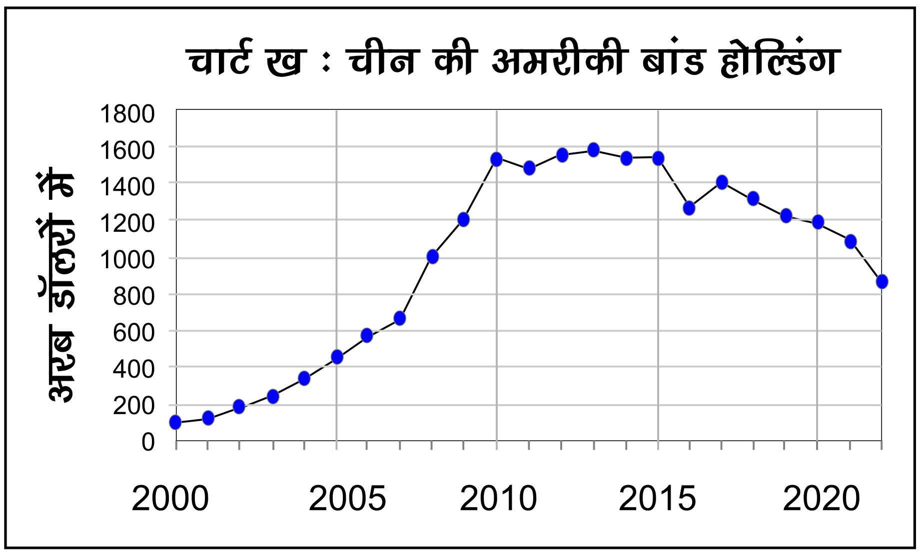

राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग

राष्ट्रीय मुद्राओं को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस्तेमाल करने के लिए देशों के बीच अनेक समझौते हुए हैं। उदाहरण के लिए, चीन और ब्राजील ने अपनी–अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार करने के लिए एक समझौता किया है। वे अमरीकी डॉलर के उपयोग के बिना, ब्राजीलियाई रियाल के लिए चीनी रेनमिनबी (आर.एम.बी.) मुद्राओं का आदान–प्रदान करने पर सहमत हुए हैं। हाल ही में, सऊदी अरब, केन्या और संयुक्त अरब अमीरात ने भी अपनी–अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में पेट्रोलियम उत्पादों का व्यापार करने के लिए सौदे किए हैं।

चीन ने 2009 में आर.एम.बी. क्रॉस–बॉर्डर ट्रेड सेटलमेंट पायलट स्कीम की शुरुआत की थी, जिसके ज़रिये कंपनियों को डॉलर के बजाय आर.एम.बी. में व्यापारिक भुगतान को निपटाने की अनुमति मिलती है। तब से चीन ने 30 से अधिक देशों और क्षेत्रों के साथ मुद्रा विनिमय समझौते स्थापित करके व्यापारिक भुगतान के निपटान में आर.एम.बी. के इस्तेमाल का विस्तार किया है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो एक विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना है और जो 60 से अधिक देशों और क्षेत्रों तक फैली हुई है, उसमें आर.एम.बी. के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दे रहा है।

हिन्दोस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस साल अप्रैल की शुरुआत में घोषणा की थी कि हिन्दोस्तान और मलेशिया के बीच व्यापार अब हिन्दोस्तानी रुपये में किया जा सकेगा। इससे पहले भारतीय रिज़र्व बैंक ने घोषणा की थी कि रुपये में सीमा पार व्यापार करने के लिए कई दक्षिण एशियाई देशों के साथ बातचीत चल रही है। हिन्दोस्तानी रुपया व्यापारिक भुगतान तंत्र में कई अन्य देशों ने अपनी रुचि दिखाई है। ताज़िकिस्तान, क्यूबा, लक्जमबर्ग और सूडान ने इस तंत्र का उपयोग करने के बारे में हिन्दोस्तान से बातचीत शुरू कर दी है। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के पश्चात, अमरीकी प्रतिबंध लगने के बाद रूस द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। हिन्दोस्तान अब इस तंत्र में उन और देशों को शामिल करना चाहता है जिनके पास डॉलर की कमी है।

ब्रिक्स समूह, जिसमें ब्राजील, रूस, हिन्दोस्तान, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, उसने जून 2009 में ही घोषणा कर दी थी कि एक नई वैश्विक रिज़र्व मुद्रा की आवश्यकता है। 30 मार्च, 2023 को रूस के राज्य ड्यूमा (रूस की संसद) के उपाध्यक्ष अलेक्जेंडर बाबाकोव ने कहा कि ब्रिक्स एक "नई मुद्रा" विकसित करने पर काम कर रहा है जिसे अगस्त 2023 में, डरबन में होने वाले ब्रिक्स के आगामी शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा।

दक्षिण–पूर्व एशिया के दस देशों, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर और मलेशिया के ए.एस.ई.ए.एन (आसियान) समूह के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों ने अप्रैल 2023 में मुलाक़ात की। उन्होंने अमरीकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और स्थानीय मुद्राओं में भुगतान को निपटाने के तरीक़ों पर चर्चा की।

विदेशी मुद्रा भंडार का डी–डॉलराईज़ेशन

डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में व्यापार करने की प्रवृत्ति के साथ–साथ दुनिया के विभिन्न राज्यों द्वारा रखे गए विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। यह हिस्सेदारी 2002 में 67 प्रतिशत थी जो से 2022 में घटकर 58 प्रतिशत हो गई है (चार्ट–क देखिये)। 1970 के दशक में अमरीकी डॉलर सभी विदेशी मुद्रा भंडारों का लगभग 85 प्रतिशत हुआ करता था। वैश्विक भंडार में यूरो की हिस्सेदारी 2012 तक बढ़कर 24 प्रतिशत हो गई और तब से इसमें कुछ गिरावट आई है। यूरो के अलावा, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड के शेयर लगभग 5 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। चीनी रेनमिनबी का हिस्सा 3 प्रतिशत से थोड़ा कम है।

चीन, जापान और तेल उत्पादक पश्चिम एशियाई देशों ने अपने व्यापार में निर्यात की बहुतायत के कारण अमरीकी डॉलर जमा कर लिये थे। वे अपने बेशी डॉलरों से अमरीकी ट्रेज़री बांड ख़रीद रहे थे। वे अब डॉलर के प्रति अपना जोखि़म कम कर रहे हैं। 2010 के बाद से चीन की अमरीकी बांड होल्डिंग में कमी को चार्ट–ख में दिखाया गया है।

सोने के भंडारों में बढ़ोतरी

काग़जी (फिएट) मुद्राओं, जिनका स्वयं कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है और न ही वे वास्तविक मूल्य वाली किसी भी चीज के मूल्य से जुड़ी होती हैं, सोना मूल्य का एक विश्वसनीय भंडार होता है। कई देश अमरीकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने और किसी भी बड़े वैश्विक आर्थिक पतन से अपना बचाव करने के लिए सोना ख़रीद रहे हैं।

सितंबर 2021 और मई 2023 के बीच बड़ी मात्रा में सोना खरीदने वाले कुछ केंद्रीय बैंक हैं – चीन (128.5 मीट्रिक टन), हिन्दोस्तान (91.6 मीट्रिक टन) और तुर्किये (88.2 मीट्रिक टन)। 2022 में 30 मीट्रिक टन से अधिक सोना ख़रीदने वाले देशों में मिस्र, इराक, कतर और रूस शामिल हैं। केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की ख़रीद के लिए 2023 की पहली तिमाही रिकॉर्ड स्थापित करने वाली तिमाही थी, जिसमें केंद्रीय बैंकों ने कुल मिलाकर 228 मीट्रिक टन की ख़रीदारी की, जिसमें अकेले सिंगापुर की 68.7 मीट्रिक टन की हिस्सेदारी थी।

निष्कर्ष

जबकि अमरीकी डॉलर अब तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा बतौर क़ायम है, कई देश इस मुद्रा पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अन्य मुद्राओं में व्यापार करने और अपने विदेशी मुद्रा भंडार में अमरीकी डॉलर की हिस्सेदारी कम करने के तरीक़ों पर काम कर रहे हैं। वे खुद को अमरीकी प्रतिबंधों से सुरक्षित बनाने और अमरीका की अस्थिर मौद्रिक नीति से उत्पन्न होने वाले जोखि़मों के प्रति अपने आप को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं।

http://hindi.cgpi.org/23817

अमरीकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने का एक प्रमुख कारण अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा इसे आर्थिक और भू–राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना है। जिन देशों को अमरीका अपना विरोधी मानता है, उन्हें व्यापारिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है और उनके डॉलर खातों को फ्रीज़ कर दिया गया है।

मज़दूर एकता लहर (इंटरनेट संस्करण)
हिन्दी : hindi.cgpi.org, **अंग्रेजी :** www.cgpi.org,
मराठी : marathi.cgpi.org
पंजाबी : punjabi.cgpi.org, **तामिल :** tamil.cgpi.org
ई मेल : mazdoorektalehar@gmail.com, Ph.09868811998, 09810167911

ब्रिटेन में डॉक्टरों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल की

13 जुलाई, 2023 को हजारों जूनियर डॉक्टरों ने पांच दिवसीय हड़ताल शुरू की। ये डाक्टर ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस (एन.एच.एस.) में अपने कैरियर के शुरुआती चरण में हैं। इस हड़ताल को ब्रिटेन की स्वास्थ्य प्रणाली के इतिहास की सबसे लंबी हड़ताल बताया जा रहा है।

जूनियर डॉक्टरों ने बताया है कि मुद्रास्फीति ने उन्हें मिलने वाले वेतन के प्रभावी मूल्य को कम कर दिया है। डॉक्टरों की यूनियन, ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन (बी.एम.ए.) ने मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए, जूनियर डॉक्टरों के वेतन को 2008 के स्तर पर वापस लाने के लिए 35 प्रतिशत वेतन वृद्धि की मांग की है। जबकि सरकार ने 6 प्रतिशत वेतन वृद्धि का प्रस्ताव किया है। सरकार का प्रस्ताव न केवल पिछले 15 वर्षों में वेतन की ख़रीद क्षमता में हुई कमी को पूरा नहीं करता है, बल्कि इस साल की महंगाई के अनुसार भी नहीं है। 2008 के बाद से जूनियर डॉक्टरों के वेतन में 26 प्रतिशत की गिरावट आई है अगर महंगाई से हुए असर को साथ लिया जाये।

यह डॉक्टरों की चौथी हड़ताल है। इससे पहले 14 जून को क़रीब 50,000 जूनियर डॉक्टरों ने इसी मांग को लेकर हड़ताल की थी। वह हड़ताल 72 घंटे तक चली और उनके वेतन और कामकाज की हालतों पर चल रहे हमलों के ख़िलाफ़ सभी स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के एकजुट और निरंतर विरोध का हिस्सा थी।

बढ़ती मुद्रास्फीति के अनुसार वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर डॉक्टरों का प्रदर्शन

अप्रैल और मई में भी डॉक्टरों ने हड़ताल की, लेकिन हर बार सरकार ने उनके साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया और बहुत ही मामूली प्रस्ताव किए। 2022 में, सरकार ने अपने वेतन समीक्षा बोर्ड के ज़रिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों को लगभग 3.5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि का प्रस्ताव किया था, जो मुद्रास्फीति से काफी कम था।

डॉक्टरों को पता है कि हड़ताल की कार्रवाई से स्वास्थ्य सेवा पर असर पड़ेगा, लेकिन उनके पास हड़ताल पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने ब्रिटेन सरकार से बातचीत करने का आग्रह किया है, लेकिन सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। सरकार कई सार्वजनिक क्षेत्रों के मज़दूरों द्वारा की जा रही हड़तालों का सामना कर रही है, लेकिन वह इस बात पर अड़ी हुई है कि जब तक हड़तालें होंगी तब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी।

सरकार ने हड़ताली डॉक्टरों को बदनाम करने और जनता को हड़ताली डॉक्टरों के ख़िलाफ़ भड़काने में जरा भी समय नहीं गंवाया। उसने घोषणा की है कि "35 प्रतिशत की वेतन वृद्धि की मांग मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए जोखिम है, जो हर किसी को ग़रीब बनाती है।" यह सरासर झूठ है। उच्च वेतन से मुद्रास्फीति नहीं बढ़ती है; दूसरी ओर, मज़दूर सभी वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती क़ीमतों का सामना करने में सक्षम होने के लिए उच्च मज़दूरी की मांग करने के लिए मजबूर हैं। सभी उपभोक्ता वस्तुओं की क़ीमतें मई 2023 में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत बढ़ी हैं।

रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग की नर्सों, विभिन्न सरकारी अस्पतालों के एम्बुलेंस कर्मचारियों और जूनियर डॉक्टरों की हालिया हड़तालों को देशभर के कामकाजी लोगों से लगातार समर्थन मिला है। अन्य कामकाजी लोग स्वास्थ्य कर्मियों की वेतन संबंधी चिंताओं की वास्तविकता को पहचानते हैं और वे जानते हैं कि सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं देती है।

http://hindi.cgpi.org/23808

समान नागरिक संहिता पर बहस

पृष्ठ 1 का शेष

भागीदार होने के नाते, महिलाओं को मिलने चाहियें। इस संघर्ष का सभी प्रगतिशील ताक़तों ने समर्थन किया है। इस संघर्ष ने सभी मौजूदा सामाजिक मामलों से संबंधित क़ानूनों – धर्म पर आधारित क़ानूनों तथा सामान्य क़ानूनों – में तरह–तरह के सुधारों की ज़रूरत पर रोशनी डाली है।

जिन हालतों में यू.सी.सी. पर मौजूदा बहस शुरू की गई है, उससे पता चलता है कि इसका मक़सद महिलाओं के ख़िलाफ़ भेदभाव की समस्या को दूर करना नहीं है।

सबसे पहले, केंद्र सरकार 21वें विधि आयोग की सिफ़ारिशों का कोई ज़िक्र नहीं कर रही है। 2018 में 21वें विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत एक पेपर में कहा गया है कि, "इस आयोग का मानना है कि ग़ैर–बराबरी की जड़ भेदभाव है, न कि भिन्नता। इस ग़ैर–बराबरी को दूर करने के लिए, आयोग ने मौजूदा पारिवारिक क़ानूनों में कई तरह के संशोधनों का सुझाव दिया है... इसलिए इस आयोग ने समान नागरिक संहिता पेश करने के बजाय, ऐसे क़ानूनों पर विचार किया है जो भेदभावपूर्ण हैं। समान नागरिक संहिता इस समय नहीं चाहिए, न ही इसकी ज़रूरत है।" केंद्र सरकार ने इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि उसने 21वें विधि आयोग के इन निष्कर्षों की उपेक्षा क्यों की है।

दूसरे, यू.सी.सी. के पक्ष में मौजूदा आह्वान और अभियान 21वें विधि आयोग की सिफ़ारिश के बिल्कुल विपरीत दिशा में एक क़दम है। भाजपा नेता यू.सी.सी. की वकालत करते हुए महिलाओं के ख़िलाफ़ भेदभाव के बजाय, भिन्नता को मुख्य मुद्दा बना रहे हैं।

तीसरा, 22वां विधि आयोग, जिसे 21 फरवरी, 2020 को अधिसूचित किया गया था, अपने तीन साल के कार्यकाल के दौरान अधिकांश समय बिना किसी सदस्य के रहा। इसके अध्यक्ष ने 9 नवंबर, 2022 को ही पदभार ग्रहण किया था और इसका कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे लगता है कि इस निकाय द्वारा यू.सी.सी. पर शुरू की गयी बहस का उद्देश्य 2024 के लोकसभा चुनावों को प्रभावित करना है।

चौथा, जब पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय लोगों के कई संगठनों ने यू.सी.सी. पर आपत्तियां उठाई थीं, तो संबंधित केंद्रीय मंत्री ने यह जवाब दिया कि इन लोगों को यू.सी.सी. से बाहर रखा जा सकता है।

इन सारे तथ्यों को मिलाकर देखा जाये तो स्पष्ट हो जाता है कि यू.सी.सी. को लेकर वर्तमान अभियान का निशाना ख़ास तौर पर मुस्लिम सामाजिक मामलों से संबंधित क़ानून हैं, जिन्हें पिछड़े और प्रतिक्रियावादी रंगों में चित्रित किया जा रहा है।

हमारे देश में धर्म पर आधारित भेदभावपूर्ण सामाजिक मामलों से संबंधित क़ानूनों के ख़िलाफ़ संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। ब्रिटिश हुक्मरानों ने ही अलग–अलग धर्म–आधारित पारिवारिक/सामाजिक क़ानूनों को लिखित रूप में संहिताबद्ध किया था। उन्होंने हिन्दोस्तानियों को सांप्रदायिक आधार पर बांटने तथा पिछड़े रीति–रिवाजों के बोझ तले दबाकर रखने के लिए ऐसा किया था।

सभी महिलाओं के समान अधिकारों की मान्यता के लिए, महिलाओं और सभी प्रगतिशील ताक़तों ने अनवरत संघर्ष किया है। इस संघर्ष की वजह से, संविधान सभा को 1950 के संविधान में "राज्य के नीति–निदेशक तत्वों" में से एक के रूप में, समान नागरिक संहिता को शामिल करना पड़ा था। परन्तु, यह क़ागज़ पर ही रह गया है, क्योंकि हुक्मरान सरमायदार वर्ग के लिए मेहनतकश जनता को बांटकर रखना और उपनिवेशवादी तौर–तरीक़ों से हुकूमत को जारी रखना ज्यादा फ़ायदेमंद रहा है। हुक्मरानों ने मेहनतकश जनता के शोषण और उत्पीड़न को तेज़ करने के लिए, महिलाओं की दबी–कुचली स्थिति के साथ–साथ, समाज के हर तरह के पिछड़ेपन का इस्तेमाल किया है। हुक्मरान वर्ग ने तरह–तरह के धार्मिक अधिकारियों को सामाजिक मामलों से संबंधित क़ानूनों के संरक्षक के रूप में बढ़ावा दिया है।

सरमायदारों की राजनीतिक पार्टियां वास्तव में महिलाओं के ख़िलाफ़ भेदभाव को खत्म करने के लिए सामाजिक मामलों से संबंधित क़ानूनों में सुधार करने में रुचि नहीं रखती हैं। जो सरमायदारी पार्टियां समान नागरिक संहिता की ज़रूरत की बात करती हैं, वे सिर्फ़ हिंदुओं में मुस्लिम–विरोधी भावनायें भड़काने के लिए ऐसा करती हैं। हकीक़त यह है कि मुस्लिम और हिंदू, दोनों महिलाएं भेदभाव और उत्पीड़न की शिकार हैं, साथ ही अन्य धार्मिक समुदायों की महिलाएं भी।

महिलाओं के ख़िलाफ़ भेदभाव करने वाले क़ानूनों में सुधार लाने का संघर्ष समाज में सभी प्रकार के शोषण और दमन को समाप्त करने के संघर्ष का हिस्सा है। इस संघर्ष को एक ऐसे राज्य की स्थापना करने के नज़रिए से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जो सभी मनुष्यों के अधिकारों को मान्यता देता है और उनका आदर करता है; एक ऐसा राज्य जो महिलाओं के ख़िलाफ़ भेदभाव करने वाले सभी विचारों और रीति–रिवाजों को मिटाने के लिए लगातार संघर्ष करता है।

http://hindi.cgpi.org/23836

राजस्थान के किसानों की शानदार जीत

पृष्ठ 1 का शेष

के हित के लिये काम करती हैं। मज़दूरों और किसानों का शोषण बढ़ाकर कैसे पूंजीपतियों के मुनाफ़े की अमिट भूख को पूरा करना – यही उनका काम है।

किसानों को मज़दूरों के साथ मिलकर संघर्ष को इस दिशा में ले जाना पड़ेगा कि पूंजीपतियों के राज के स्थान पर मज़दूरों और किसानों का राज स्थापित किया जाये। नोहर–भादरा के किसानों को अपनी एकता को मज़बूत करते हुये, अपने संघर्ष को इसी नज़रिये से चलाना होगा।

http://hindi.cgpi.org/23831

सिंचाई के पानी की पूर्ती में कमी को लेकर, नोहर और भादरा के किसानों का अमरसिंह ब्रांच पर प्रदर्शन (फाइल फोटो, 2022)

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय कमेटी का अखबार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT U (SE)-38/2022-23

Posting Date at DLPSO, 1 & 2 Aug, 2023, Date of publish - 1 Aug, 2023

To ....

....

....

....

....

....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020 email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp
9868811998

मज़दूरों, किसानों और महिलाओं ने मणिपुर में शांति बहाल करने की मांग बुलंद की

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

25 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली के जंतर–मंतर पर मणिपुर के पीड़ित लोगों के समर्थन में तथा वहां शांति बहाल करने की मांग को उठाते हुए, एक धरना आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम दिल्ली की ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच की अगुवाई में आयोजित किया गया।

आल इंडिया किसान संगठन (ए.आई.के.एस.) तथा आल इंडिया एग्रिकल्वरल वर्कर्स यूनियन (ए.आई.ए.डब्ल्यू.यू.) से जुड़े किसानों सहित पुरोगामी महिला संगठन की महिला कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

प्रदर्शनकारियों के हाथों में प्लेकार्ड व बैनर थे, जिन पर नारे लिखे हुए थे : "मणिपुर सहित सभी पूर्वोत्तर राज्यों से आफ्स्पा को हटाओ!", "मणिपुर में राजकीय आतंक व हिंसा मुर्दाबाद!", "हुक्मरान पूंजीपति वर्ग की 'फूट डालो और राज करो' की नीति मुर्दाबाद!", "महिलाओं पर हिंसा फैलाने वाले गुनहगारों को सज़ा दो!", इत्यादि। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राज्य की एजेंसियों को दोषी ठहराते हुए, ज़ोरदार नारे दिए गए।

सहभागी यूनियनों – एटक, सीटू, मज़दूर एकता कमेटी, एच.एम.एस, ए.आई.

यू.टी.यू.सी., सेवा, एल.पी.एफ., यू.टी.यू.सी., आई.सी.टी.यू., पुरोगामी महिला संगठन, ए.आई.ए.डब्ल्यू.यू. – के प्रतिनिधियों ने धरने को संबोधित किया।

धरने को संबोधित करते हुए, वक्ताओं ने केन्द्र सरकार और मणिपुर सरकार को मणिपुर की मौजूदा दर्दनाक स्थिति के लिए ज़िम्मेदार ठहराया और उनकी कड़ी निंदा की।

वक्ताओं ने सरकार द्वारा उन अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की आवाज़ों को दबाने के प्रयासों की निंदा की, जिन्होंने मणिपुर की वर्तमान स्थिति में सरकार और राज्य प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाये हैं।

मणिपुर के लोगों की भयानक हालतों का विवरण करते हुए, वक्ताओं ने बताया कि मणिपुर में 3 मई, 2023 से अराजकता और हिंसा फैल रही है। इसके चलते 150 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। लोगों के घर और आजीविका के साधन नष्ट हो गए हैं। राजधानी इंफाल सहित विभिन्न शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में हथियारबंद गिरोहों ने लोगों, उनके घरों और संपत्तियों को निशाना बनाया है। महिलाओं के ख़िलाफ़ जघन्य अपराधों को अंजाम दिया गया है। इन सभी अपराधों को फ़ौजी शासन की निगरानी में अंजाम दिया गया है। हजारों की संख्या में लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। परिणामस्वरूप पड़ोसी राज्यों के साथ–साथ म्यांमार में शरणार्थी शिविरों में एक लाख से अधिक लोग अमानवीय परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं।

वक्ताओं ने यह स्पष्ट किया कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे, राज्य व उसकी एजेंसियों द्वारा लोगों को बांटने और क़त्लेआम आयोजित करने की घिनावनी हरकतें साफ़–साफ़ नज़र आ रही हैं।

प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि मणिपुर में फ़ौरन हिंसा रोकने और शांति बहाल करने के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार ठोस क़दम उठाएं और पीड़ित लोगों को फ़ौरन राहत पहुंचाएं तथा उनके पुनर्वास का इंतज़ाम करें। स्कूलों को फिर से खोलने और इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने की मांग की गई।

कार्यक्रम के अंत में इन मांगों के साथ गृहमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया।

http://hindi.cgpi.org/23751

पाठकों की प्रतिक्रिया

हिंद–अमरीकी सांझेदारी हिन्दोस्तान के लिये ख़तरनाक

संपादक महोदय,

मज़दूर एकता लहर में प्रकाशित 'हिंद–अमरीकी सांझेदारी हिन्दोस्तानी लोगों के हित में नहीं है' – लेख का यह शीर्षक साफ़ तौर पर दर्शाता है कि हिन्दोस्तान का शासक वर्ग पूरे विश्व में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है और दूसरी तरफ़ अमरीका हिन्दोस्तान के पूंजीपतियों के साम्राज्यवादी मंसूबों और चीन के साथ उनके अंतर्विरोधों का फ़ायदा उठा रहा है।

यह सर्वविदित है कि अमरीका के पुराने दोस्तों, अर्थात जिन देशों से उसने दोस्ती की, उन पुराने दोस्तों का क्या हश्र हुआ। राष्ट्रीय संप्रभुता का हनन करने में अमरीका का सबसे लंबा इतिहास रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो आतंकवाद का ख़ात्मा करने की आड़ में अमरीका ने अफ़गानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया जैसे कई देशों पर जंग किए हैं। इन युद्धों में उसने करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों को ख़त्म किया है और उन देशों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। दुनिया यह जानती है कि इसके पीछे उसका असली मक़सद क्या था। वह वहां के तेल और खनिजों को हथियाना और अपने आतंक को विश्व में क़ायम करना चाहता था। गौरतलब है कि हम सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है और यह जानने की ज़रूरत है कि हमारे देश के पूंजीपति अन्य देशों में अपने साम्राज्य का झंडा लहराना चाहते हैं। पूरे विश्व पर एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं। पूंजीपति मज़दूरों और किसानों को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें उनके लक्ष्य से भटका रहे हैं।

हमारे देश का युवा वर्ग ग़रीबी से परेशान है और नौकरी की तलाश में भटक रहा है। जहां समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य सेवा, सबको रोज़गार के अवसर जैसे बड़े–बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं। वहीं हमारे देश के मज़दूरों, किसानों, औरतों और नौजवानों के सामने समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। मज़दूर, किसान भूख और ग़रीबी से बदहाल हैं तथा देश की सशक्त शक्ति कहलाने वाला युवा वर्ग बेरोज़गारी की समस्या से जूझ रहा है।

इन सभी समस्याओं को जानते हुए भी, पूंजीपति वर्ग भ्रम पैदा कर रहा है और राजनीति की आड़ में लोगों को गलत दिशा में ले जा रहा है। पूंजीपति वर्ग बड़े–बड़े शब्दों जैसे कि एकता, समानता, प्रगतिशील विकास का प्रयोग करके लोकतंत्र के नाम पर अपना उल्लू सीधा करने की ताक में लगा हुआ है। जैसा कि हम देखते हैं कि देश की मुख्य समस्याओं को जानबूझकर नज़रंदाज़ करके, हमारे देश के प्रधानमंत्री अमरीका का दौरा करके 24,600 करोड़ रुपए की कुल क़ीमत वाले युद्ध में इस्तेमाल होने वाले कई युद्धक हथियारों, 31 एम.क्यू. 9–बी ड्रोन हवाई जहाज ख़रीदने जैसे कई समझौते कर रहे हैं।

यह साफ़ तौर पर दर्शा रहा है कि इससे अमरीकी कंपनियों को बहुत बड़े पैमाने पर बेशुमार मुनाफ़ा होगा। जितने रुपये इन हथियारों की ख़रीद पर खर्च किये जा रहे हैं, इन करोड़ों रुपयों को देश की जनता से वसूला जाएगा। यह हमें दिख रहा है कि यह समझौता जनता के हित में नहीं है। इससे मज़दूरों और किसानों के हालात और भी बदतर हो जाएंगे।

ये समझौते साफ़–साफ़ दर्शाते हैं कि अमरीका से दोस्ती करना देश के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। इस जंगी योजना में हिन्दोस्तानी लोगों को ही तोप के चारे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।

इसलिए मज़दूर बतौर हमारा यह कर्तव्य है कि औरों को जागरुक बनाएं और हिंद अमरीकी गठबंधन का खुलकर विरोध करें। अमरीकी साम्राज्यवाद को हमारे देश में घुसने से रोकना होगा तथा दक्षिणी एशिया में शांति बहाल करने के लिए अमरीकी साम्राज्यवाद को भगाना होगा। देश में मज़दूरों और किसानों का राज्य स्थापित करके समाजवाद को लाना ही हमारा फौरी कर्तव्य होना चाहिए और इस दिशा में हमें कार्य करना होगा।

अजीत मोहन
नागपुर